'सीतापुरा-अंबाबाड़ी मैट्रो की डीपीआर 31 मार्च तक बनेगी'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में मैट्रो अलाइन्मैंट पर दिशा निर्देश दिये

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मेट्रो अलाइन्मैंट के संबंध में बैठक ली और सीतापुरा-अंबाबाड़ी मैट्रो कॉरिडोर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 31 मार्च तक पूरी करने के निर्देश दिए।

जयपुर, 11 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीतापुरा, गोनेर मोड़ से अंबाबाड़ी (टोडी मोड़) तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर (फेज-2) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का कार्य 31 मार्च, 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर के सिविल कार्यों के टेंडर 15 अगस्त से पहले जारी हों और परियोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर मेट्रो अलाइनमैंट के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जयपुर में मेट्रो सेवा के विस्तार पर गंभीरता से कार्य कर रही है। हमारी मंशा है कि भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए जयपुर के सभी क्षेत्र मेट्रो से कनैक्ट हों। मुख्यमंत्री ने फेज़-2 के अंतर्गत, सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक मेट्रो संचालन का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस परियोजना से प्रतापनगर, टोंक रोड़, सीकर रोड, विद्याधर नगर, सीतापुरा जैसे क्षेत्र मेट्रो सेवा से जुड़ेंगे और बड़ी संख्या में आमजन को मेट्रो की सुगम एवं द्रुतगामी परिवहन सुविधा मिल सकेगी।

> ■ **मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की सोच है कि भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए जयपुर के सभी क्षेत्र मैट्रो से कनैक्ट हो।**

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सीतापुरा-अंबाबाड़ी मेट्रो कॉरिडोर पर प्रस्तावित स्टेशन्स पर समुचित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल एवं प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सीएमडी वैभव गालरिया, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त आनंदी सहित, संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

पाकिस्तान में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और बलूच नागरिकों को रिहा कर दिया गया है और उन्हें सुरक्षित मार्ग से उनके गंतव्य की ओर भेजा गया है।

बीएलए ने चेतावनी दी है कि यदि सैन्य हस्तक्षेप जारी रहा, तो सभी बंधकों को मार दिया जायेगा। प्रवक्ता ने कहा कि ऑपरेशन का नेतृत्व मजीद ब्रिगेड, एसटीओएस, फतह स्क्वॉड और बीएलए की जिराब यूनिट द्वारा किया जा रहा है तथा किसी भी सैन्य कार्रवाई का निर्णायक जवाब दिया जायेगा। बीएलए के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना वहां बीएलए की यूनिटों के खिलाफ हेलीकाप्टर और ड्रोन से हवाई हमले कर रही है। यदि उसके लोगों पर वहां हवाई हमले तुरंत नहीं रोके गए तो पाकिस्तान को बंधक बनाये गये लोगों से हाथ धोना पड़ेगा और इसके लिए वही जिम्मेदार होंगे। उल्लेखनीय है कि बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक रणनीतिक अभियान चला रखा है और इसी के तहत उनकी यूनिटों ने बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर स्टेशन जा रही यात्री ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया और ट्रेन को पटरी से उतारकर उस पर कब्ज़ा कर लिया है।

जेडीए के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। जांच में यह भी सामने आया है कि अभियंता अविनाश शर्मा ने 25 योजनाओं और कॉलोनियों में संपत्ति अर्जित की है। इन योजनाओं के नियमन और डवलपमेंट में किस तरह डवलपर को फायदा पहुंचाया गया और इस प्रक्रिया में नियमों की अवहेलना हुई, इसे लेकर भी एसीबी जांच में जुटी है। इस क्रम में जेडीए के विभिन्न ज़ोन कार्यालयों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

ज़ैलैंस्की दो पाटों के बीच...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह संदेह पैदा हो रहा है कि क्या सेना एक लंबा युद्ध बरकरार रख पाएगी। ज़ैलैंस्की के पास एक कठिन विकल्प है, घटते पश्चिमी समर्थन के साथ सैन्य अभियान को जारी रखें या निराश दिखे बिना बातचीत की दिशा में आगे बढ़ें। उन्हें ऐसा रास्ता खोजना होगा, जो यूक्रेन की दृढ़ता को बनाए रखते हुए आगे और थकान न होने दे।

हालिया सर्वेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि यूक्रेन की जनता की मानसिकता में शांति के पक्ष में बदलाव आ रहा है। अगस्त से अक्टूबर 2024 तक किए गए एक गैलप सर्वेक्षण में पाया गया कि अब 52 प्रतिशत यूक्रेनी तत्काल शांति वार्ता का समर्थन करते हैं, जबकि 38 प्रतिशत अभी भी विजय तक लड़ाई जारी रखने के पक्ष में हैं। यह 2022 के बाद से एक बड़ा बदलाव है, जब 73 प्रतिशत लोग संघर्ष जारी रखने के लिए दृढ़ थे। पूर्वी यूक्रेन में, जहां युद्ध सबसे अधिक विनाशकारी रहा है, 63 प्रतिशत लोग अब बातचीत का समर्थन करते हैं, जो युद्ध की थकान को दर्शाता है। इस बदलाव के बावजूद संदेह बरकरार है। इन्फो सेपियन्स एल.एल.सी. द्वारा किए गए एक अलग सर्वेक्षण में पाया गया कि 64 प्रतिशत यूक्रेनी पश्चिमी सुरक्षा गारंटी के बिना बातचीत का विरोध करते हैं। उन्हें डर है कि रुस एक संक्षिप्त युद्ध विराम के बाद फिर से आक्रमण कर सकता है। इस बीच, 30 प्रतिशत का मानना है कि चाहे जैसे भी हो, बातचीत शुरु करनी चाहिए, यह बताते हुए कि यूक्रेन के पास लंबे युद्ध के लिए सीमित संसाधन हैं।

ज़ैलैंस्की के अगले कदम यूक्रेन के भविष्य का निर्धारण करेंगे, जिनसे यह तय होगा कि राष्ट्र विजयी होता है या समझौते के लिये ओर मजबूर होता है। और यह इस पर निर्भर करेगा कि ज़ैलैंस्की सैन्य प्रतिरोध और कूटनीतिक रणनीति को कैसे संतुलित करते हैं।

भारी पड़ा एलन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कम्यूनिकेशंस सैटेलाइट के उपयोग के लिये पोलैंड पैसे दे रहा है, यूक्रेन इसका उपयोग मुफ्त में नहीं कर रहा है।

एलन मस्क ने पोलैंड के विदेश मंत्री से अनावश्यक लड़ाई मोल ले ली है। पोलैंड के विदेश मंत्री ने तो यूक्रेन को दी गई इन धमकियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम के जरिये, यूक्रेन को मिल रहीं सभी फ्रन्टलाइन कम्यूनिकेशन तथा इंटेलिजेन्स सुविधाएं वापस ले ली जायेंगी।

एलन मस्क ने कहा था कि स्टारलिंक लिंक्स की सहायता के बिना, रूस के खिलाफ यूक्रेन की फ्रन्टलाइन धराशायी हो गई होती। आखिरकार मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम के मालिक हैं। उन्होंने अपनी शेखी बघारते हुए कहा था कि स्टारलिंक के सहयोग बिना, यूक्रेन, रूस के सामने टिक ही नहीं सकता था।

इसके जवाब में, पोलैंड के विदेश मंत्री ने खुलेआम कहा कि यूरोपियन देशों को जल्दी ही अमेरिका के स्टारलिंक इन्फ्रास्ट्रक्चर से दूर हो जाना चाहिये। इस मामले में, फ्रांस की यूटैलसैट उत्कृष्ट सेवाएं दे रही है तथा वह बड़ी आसानी से मस्क की कम्पनी की जगह ले हो सकती है। मस्क को अपनी मूर्खता का अहसास हो गया तथा उन्होंने इस स्थिति को रफा-दफा करने की दिशा में तुरन्त ही कदम उठाये। उन्होंने कहा कि वे इस कम्पनी के मालिक जरूर हैं, लेकिन वे एकाएक यूक्रेन को सेवाएं देना बंद नहीं करेंगे।

सच तो यह है कि यूरोपियन देशों की कम्यूनिकेशन सेवाओं को सहयोग देने से मस्क को अच्छा-खासा और बड़े मुनाफे का बिज़नैस मिल रहा है।

पंजाब में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को मौके से खदेड़ दिया। हालांकि, बाद में प्रशासन की टीम को लौटना पड़ा। किसानों का आरोप है सरकार से उन्हें जमीनों का उचित मुआवजा नहीं मिला है। इसलिए, वे अपनी जमीनों पर खेती कर रहे हैं। जबकि, जिला प्रशासन के अधिकारी कहते हैं कि किसानों को जमीनों का मुआवजा मिल गया है, तो ये जमीनें अब सरकार की हैं। इन पर किसानों को खेती का हक नहीं है। घटना के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बयान जारी कर कहा है कि गुरदासपुर के नंगल चौड़ और भरथ में किसानों को मुआवजा दिए बिना जमीन हथियाने की कोशिश की गई है। जब किसानों ने उसका विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया गया।

'क्या ठोकना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा ऐसी भाष निंदनीय है। इसके बाद खड़गे ने सदन में खड़े होकर कहा, 'मैंने आसन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने उपसभापति से कहा कि अगर आपको मेरी बातों से ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मैंने ठोको शब्द का इस्तेमाल सरकार की नीतियों के लिए किया है। मैं सरकार से माफी नहीं मांगूंगा।'

लैंड फॉर जॉब घोटाला: लालू परिवार को बड़ी राहत, सभी को जमानत मिली

पटना, 11 मार्च। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में मंगलवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने आरोपियों को 50 हजार रुपये मुचलके और इतनी ही राशि के एक सिक्योरिटी बॉन्ड के साथ राहत दी है।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि इस मामले में लालू व तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 8 आरोपियों को पेश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो सीबीआई की पहली और दूसरी चार्जशीट में पेश हो चुके हैं। पिछली सुनवाई में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया था। आरोपियों को 11 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने हेमा, तेज प्रताप यादव व अन्य को समन भेजा था। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू परिवार समेत 103 लोग आरोपी हैं। इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। दरअसल पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है उस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे।

केजरीवाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। पुलिस को 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट भी देनी होगी। यह मामला 2019 का है। तब एक शिकायत दर्ज कराई गई थी।

नागौर में दो भीषण सड़क हादसों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नागौर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल नागौर चौकी प्रभारी जगदीश बिश्नोई के अनुसार, डेह से आगे लालदासजी महाराज धाम के पास मंगलवार अलसुबह एक बस पलटी खा गई, जिससे तीन जनों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 24 से अधिक लोग घायल हो गए। बस पलटने से चीख-पुकार मच गई। मरने वालों की पहचान जोधपुर निवासी हर्षित, आरुषि व आरव के रूप में हुई है। ये सभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी बताए जा रहे हैं, जबकि घायलों को डेह में प्राथमिक उपचार के बाद नागौर के जेएलएन अस्पताल रैफर किया गया। नागौर लाए गए घायलों में भानु, साक्षी, मोहम्मद, वेद, वासुदेव, वृंदा आदि शामिल हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जोधपुर लॉ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी पटियाला से वापस जोधपुर लौट रहे थे।

'100 और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पहले जारी किए गए 100 और 200 रुपये के सभी पुराने नोट भी प्रचलन में बने रहेंगे और वे वैध मुद्रा माने जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि यह कदम नकदी की आपूर्ति को बनाए रखने और बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600